(b) All possible measures have been taken against such movements and activities of Naga hostiles.

## P&T Quarters in Palghat (Kerala)

2597. Shri P. Kunhan: Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) the amount allotted for the construction of quarters for P&T Employees in Palghat District, Kera'a during 1964-65 and 1965-66; and
- (b) the number of quarters constructed and the amount spent?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) No specific amount was allotted during these years for construction of quarters in Palghat District.

(b) No quarters were constructed and no amount was spent.

## दिल्ली में प्राथमिक स्कूतों के श्रध्यापकों की नियुक्ति

2598. श्री प्रकाशवीर शास्त्री: श्री श्रीकार लाल बेरबा: श्री प्रिय गुप्त: श्री बड़े: श्री हकम चन्द कछशाय:

क्या शिक्षा मन्नी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने प्राथमिक स्कूलों के ग्रष्टगा कों के पदों पर नियुक्तियां, इसी प्रयोजन के लिये गत वर्ष जून में हुई परीक्षा का परिणाम घोषित किये बिना ही कर दी हैं; ग्रौर
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षामन्त्री (श्रीमु० क० चागला): (क) ग्रौर (ख). नई दिल्ली नगरपालिका से ग्रपेक्षित सूचना एकवितं की जा रही है भ्रौर यथासमय सभा पटल पर रखादी जाएगी।

दिल्ली के स्कुलों में स्थान की कमी

2599. श्री प्रकाशवीर शास्त्री:

श्री हुकम चन्द कछत्रायः

श्रीबड़े:

श्री ग्रोंकार लाल बेरवाः श्री प्रियं गुप्तः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त मिडिल स्कूलों में स्थान की बड़ी कमी है तथा प्रत्येक कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या 40 होती है ; भीर
- (ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इन स्कूलों में किसी भी कक्ष, में जिद्य,यियों की संख्या 25–30 से ग्रिधिक नहों।

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला):
(क) ग्रीर (ख) दिल्ली प्रशासन ग्रीर दिल्ली नगर निगम से ग्रेपेक्षित सूचना एकत की जा रही है ग्रीर यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दी प्रतिस्टेंटों के लिये परीक्षा 2600 थी प्रकासवीर सास्त्री:

श्रीदृकम् अन्द कञ्जगयः श्रीदृष्टेः

भी बड़े:

श्री प्रिगगुन्तः

श्री ग्रोंकार लाल बेरवा:

क्या गृह-कार्य मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दी ग्रसिस्टेंटों के पदों के ग्रसिरिक्त संघ लोक सेवा ग्रायोग ने कित-किन पदों के लिये परीक्षाएं की ; ग्रीर (ख) उनके मंत्रालय द्वारा हिन्दी ग्रसि-स्टेंटों के पदों पर नियुक्तियां करने के क्या कारण हैं जबकि इन पदों को नियमित केन्द्रीय सेवा में शामिल नहीं किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण भुक्ल): (क) सम्भवतः अन्य ऐसे असंवर्गीय पदों की ओर संकेत है जिनके लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी। यदि ऐसा है तो, उत्तर यह है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी आशुलिपिकों के असंवर्गीय पदों के लिये भी एक परीक्षा ली गई थी।

(ख) गृह मतालय का सम्बन्ध केन्द्रीय सिवालय के सभी पदों में भर्ती के लिये सामान्य सिद्धान्तों से है, फिर चाह वे नियमित केन्द्रीय सेवाओं में सिम्मिलित हों अथवा नहीं । तदनुसार ही, हिन्दी सहायकों पदों पर भर्ती के लिये एक से स्तर की व्यवस्था करने की दृष्टि से 1959 में सब लोक सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा कराने का निर्णय किया गया था।

## Indian Postal Orders

2601. Shri Jedhe: Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Indian Postal Order for the highest denomination is rupees ten only;
- (b) whether it is also a fact that the U.P.S.C. and various Universities and Public Service Commissions accept only Indian Postal Orders for payment of their fees for which public have to purchase many postal orders of rupees ten only;
- (c) if so, whether in the interest of economy of paper, Government propose to issue I.P.Os. of the denominations of Rs. 50 and Rs. 25; and
- (d) if so, when the I.P.Os. of higher denominations are likely to be available in the Post Offices?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) Yes, Sir, Under Section 45 of the I.P.O. Act 1898, the Central Government is not empowered to issue I.P.Os. for denomination beyond Rs. 10.

- (b) When fees for more than Rs. 10 have to be paid this is done by purchasing suitable number of I.P.Os. of different denominations to make up the requisite amount.
- (c) and (d). The proposal is under consideration. Amendment of the I.P.O. Act is necessary. It is not possible to indicate definitely the time by which this will be introduced.

## Indian Labour Conference

2602. Shri Madhu Limave: Shrimati Renu Chakravartty: Shri Bade: Shri D. C. Sharma: Shri Manoharan: Shri Prakash Vir Shastri: Shri S. M. Banerjee: Shri Mohammed Koya: Shri Alvares: Shri Maurya: Shri Tridib Kumar Chaudhuri: Shri A. V. Raghavan: Shri Tulsidas Jadhav: Dr. U. Misra: Shri Indrajit Gupta: Shri Prabhat Kar: Shri P. C. Borooah: Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

- (a) the conclusions of the recently held Indian Labour Conference;
- (b) whether the Industrial Truce Resolution has been repudiated by the Trade Union Organisation because of Government's failure to hold down prices, curb profits and blackmarketing; and
- (c) if so, the steps taken to save the Industrial Truce?